

ईश्वर

 subahsaverenews@gmail.com

 facebook.com/subahsaverenews

 www.subahsavere.news

 twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

वसंत और पतझड़ के मौसम में उजली मीठी धूप वाले दिन मैं जाऊँगा बस्तियों के पार एक विरल वन में जहाँ पलाश के फूलों की वंदनवार सजी होगी और महकती हवाएँ मेरा स्वागत करेंगी

पत्तियों से रिकत एक पेड़ के नीचे पीले कपड़ों में सजी एक लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी

उजास, मादकता, सुवास और निस्तब्धता से गुम्फित वह समय मेरा आनंद पर्व होगा

मैं एक दिन वहाँ जाऊँगा।

— चंद्रशेखर साकल्ले

कोशिश यही है कि हर घर में लक्ष्मी जी पधारें

- बजट पर बोले पीएम मोदी बताया ऐतिहासिक
- बजट में नारी शक्ति और युवा सोच का प्रतिबिंब

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2026 की घोषणा के बाद देश को संशोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा, ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये युवा शक्ति का बजट है। इसमें युवा सोच है, युवा के सपने हैं। इस बजट से युवाओं के लिए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा, इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को उड़ान मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।

प्रसंगवश

भारत-यूरोप संवाद : दूरदर्शी रणनीति या हालात से उपजा मोड़?

सतीश झा

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: क्या यूरोप की ओर भारत का झुकाव एक लंबा रणनीतिक नज़रिया है या वैश्विक दबावों और अमेरिकी अनिश्चितता की वजह से उठया गया एक कदम है? कूटनीति में समय ही सबसे बड़ा कारक होता है। भारत का यूरोप की ओर ताज़ा झुकाव—जिसका ठोस रूप हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) में दिखाई देता है—किसी दीर्घकालिक रणनीतिक दूरदृष्टि की पराकाष्ठा कम, और परिस्थितियों के दबाव में लिया गया एक तेज निर्णय अधिक लगता है। इतिहास बताता है कि यूरोप कभी भी भारत की रणनीतिक कल्पना के केंद्र में नहीं रहा। बदला केवल इरादा नहीं, बल्कि वह तात्कालिकता बदली जिसने वैश्विक झटकों और वॉशिंगटन में लौटती अनिश्चितता के बीच भारत को तेजी से निर्णय लेने पर विवश किया। पिछले सात दशकों तक यूरोप दिल्ली के विश्व दृष्टिकोण में परिधि पर ही रहा। भारत की विदेश नीति शीतयुद्ध के त्रिकोण से गढ़ी गई—सोवियत संघ से हथियार और ऊर्जा, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, और 1991 के बाद अमेरिका के साथ सतर्क निष्कटता। इसके उलट यूरोप भारत के लिए एक पूर्व औपनिवेशिक शक्ति और नैतिक उपदेशक बना रहा—जो मानवाधिकारों पर व्याख्यान देता रहा, लेकिन अपने बाजारों को सब्सिडी और कठोर नियमन से सुरक्षित रखता रहा। सरकार की भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी ने गहराई का वादा किया था, पर परिणाम सीमित ही रहे। शिखर सम्मेलन औपचारिक रस्मों में बदल गए, 2013 में

व्यापार वार्ताएँ ठप पड़ गईं, और व्यापार का विस्तार तो हुआ—पर बिना किसी रणनीतिक छलांग के। 2006 में जहाँ व्यापार ₹ 47 अरब था, वह 2018 में ₹ 91 अरब तक पहुँचा, पर यह वृद्धि क्रमिक थी, परिवर्तनकारी नहीं। चीन की यात्रा इसका उलटा उदाहरण पेश करती है। वॉशिंगटन के प्रारंभिक समर्थन और यूरोपीय पूंजी के प्रवाह के साथ चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से समाहित हुआ। 2000 में लगभग ₹ 100 अरब से शुरू हुआ यूरोप-चीन व्यापार आज ₹ 700 अरब से अधिक है। पैमाना, गति और केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया—तीनों ने इस उभार को कई गुना बढ़ाया। भारत को ऐसी रणनीतिक अनुकूलता कभी नहीं मिली। ब्रसेल्स की नजर में वह संरक्षणवादी, सुधारों में धीमा और मॉस्को से भू-राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ देश रहा। नतीजा यह कि दशकों तक यूरोपीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से नीचे ही अटक रही। हालिया ऑकड़े भी इसी प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। 2021 में ₹ 88 अरब से बढ़कर 2024 में भारत-ईयू वस्तु व्यापार ₹ 120 अरब तक पहुँचा। सेवाओं का व्यापार—मुख्यतः आईटी और परामर्श—तीन गुना बढ़कर ₹ 66 अरब हो गया। यह प्रगति सम्मानजनक है, पर क्रांतिकारी नहीं। इसके विपरीत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफ़टीए के साथ भारत के नए एफ़टीए लागू होते ही कुछ ही महीनों में निर्यात में तेज उछाल दिखा। यूरोप अंतिम बड़ा अपवाद बना रहा—केवल भारत की हिचक के कारण नहीं, बल्कि ब्रसेल्स की अपनी नियामक, राजनीतिक और रणनीतिक सावधानियों के चलते भी। यूरोप का यह पुनर्मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। चीन की आक्रामकता, कोविड के दौरान उजागर हुई आपूर्ति

श्रृंखला की कमजोरियाँ, और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से उपजा भू-राजनीतिक टूटाव-इन सबने भारत को एक अधिक विश्वसनीय दीर्घकालिक साझेदार के रूप में उभारा। लेकिन वास्तविक गति तब आई जब अमेरिकी व्यापार नीति में अस्थिरता लौट आई। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही भारतीय निर्यात पर शुल्क की धमकियाँ और रूस से तेल खरीद पर दंड की बातें फिर उभरने लगीं। वयों से अटकी ब्रसेल्स वार्ताओं में अचानक जान आ गई। अक्टूबर 2025 के चौदहवें दौर में सफलता मिली और जनवरी 2026 में समझौते की घोषणा हुई। आधार पहले से मौजूद था; शिखर दबाव में जाकर रखा गया। यूरोप में भारत की कूटनीति की एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करता है। हमारी विदेश नीति अब भी व्यक्ति-प्रधान और घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक है, जबकि यूरोपीय संघ जैसे जटिल साझेदार के लिए मजबूत संस्थागत निरंतरता चाहिए। ईयू से बातचीत द्विपक्षीय सौदेबाजी नहीं है। इसमें 27 सदस्य देशों, यूरोपीय आयोग और एक घने नियामक तंत्र से जूझना पड़ता है। 2007 में शुरू हुआ व्यापक व्यापार एवं निवेश समझौता पेटेंट, कृषि सब्सिडी और डेटा शासन जैसे मुद्दों पर वर्षों तक अटका रहा। प्रगति तब तेज हुई जब बाहरी झटकों—चीन का उदय और अमेरिका की नई अनिश्चितता—ने तात्कालिकता पैदा की। नया समझौता काग़ज़ पर महत्वाकांक्षी है—97 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क समाप्ति, गतिशीलता प्रावधान, रक्षा सहयोग और सतत विकास प्रतिबद्धताएँ। पर महत्वाकांक्षा अपने-आप क्रियान्वयन की गारंटी नहीं देती। असली परीक्षा समन्वय की है—क्या भारत कर-प्रणाली, श्रम बाज़ार और अनुबंध प्रवर्तन में ऐसी घरेलू

सुधार-क्षमता दिखा पाएगा जो यूरोप की नियामक अपेक्षाओं से मेल खाए? यदि यह साझेदारी वास्तव में परिवर्तनकारी बननी है, तो इसे प्रतीकवाद से आगे बढ़ना होगा। भारत की सेवाओं, औषधि उद्योग और विनिर्माण पैमाने को यूरोप की मशीनरी, सटीक इंजीनियरिंग और हरित तकनीक की ताकत से जोड़ने वाली पूरक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनानी होंगी। एक क्षेत्र विशेष रूप से गंभीरता का संकेत देगा—ग्रीन हाइड्रोजन। साझा निवेश लक्ष्य, एकरूप मानक और बड़े पैमाने पर उत्पादन का विश्वसनीय मार्ग तय हुआ, तो यह साझेदारी आने वाले औद्योगिक चरण की धुरी बन सकती है। निर्णायक तत्व संस्थागत गहराई होगी। स्थायी कार्य समूह, वार्षिक व्यापार एवं नियामक समीक्षा, और सशक्त उप-राष्ट्रीय साझेदारियाँ—जैसे गुजरात-हैम्बर्ग या कनाटक-बेवेरिया—आकस्मिक शिखर सम्मेलनों की जगह लेनी चाहिए। इसके बिना गति राजनीतिक चक्रों की बंधक बनी रहेगी। भारत का आर्थिक उत्थान बहु-दिशात्मक रणनीति की माँग करता है, न कि बाहरी झटकों से प्रेरित तात्कालिक पुनर्संरजन की। ईयू समझौता आवश्यक कदम है, पर इसे मंजिल नहीं, नींव माना जाना चाहिए। यदि दिल्ली इसे प्रतिक्रियात्मक विनिर्धोकरण का अंतिम बिंदु समझेगी, तो यूरोप एक शालीन साझेदार भर रह जाएगा—पर परिवर्तनकारी नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि यह समझौता बनने में कितना समय लगे। सवाल यह है कि क्या भारत इसे सार्थक बनाने के लिए तैयार है। इतिहास हस्ताक्षर को नहीं, उसके बाद आने वाले ठोस परिणामों को याद रखेगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बजट 2026 ‘सुधार एक्सप्रेस’

- बजट 2026 में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज
- महिला, युवा, गरीब और किसान, सबका होगा कल्याण
- बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15 फीसदी बढ़ा
- 17 कैंसर मेडिसिन ड्रग्स फ्री, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और ‘सुधार एक्सप्रेस’ को जारी रखने की घोषणा की। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया। वे 85 मिनट बोलें, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत दी।

विदेश से सामान मंगवाना होगा सस्ता, कस्टम ड्यूटी घटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश से सामान मंगवाना अब सस्ता होगा। सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते समय की। उन्होंने आयात किए जाने वाले सभी सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 20 से घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि अब बाहर से अपने लिए सामान मंगवाना सस्ता हो जाएगा। सरकार कस्टम ड्यूटी की इस व्यवस्था को आसान बनाना चाहती है। कस्टम ड्यूटी कैसे लगती है, इसे समझना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इकॉनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर बताया है कि आयातित सामानों पर बैसिक कस्टम ड्यूटी लगती है जिसमें छूट दी गई है।

‘विकसित भारत’ के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन

निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण पर जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री ने लगभग सवा घंटा के अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश करते हुए ‘विकसित भारत’ के लिए बैंकों को तैयार करने को लेकर एक समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया।



बजट की सबसे बड़ी घोषणाएं

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 फीसदी शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22 फीसदी की बढ़ोतरी। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे।

पीएम मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री का विकसित भारत @2047 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला



छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में केन्द्रीय बजट पर विषय-विशेषज्ञों से

संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सगहना हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रफ़ॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया।

‘गोल्डीलॉक्स’ माहौल में आर्थिकी को सुनहरा टच देने की कोशिश

त्वरित टिप्पणी/ बजट 2026-27 अजय बोकिल

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अपने लगातार 9वें वार्षिक बजट में तात्कालिक और लोक-लुभावन लाभों की जगह चुनौतीपूर्ण माहौल में दीर्घावधि में देश का आर्थिक संरचना और स्थिरता को मजबूती देने पर ज्यादा जोर दिया है, जो आज वैश्विक आर्थिक राजनीतिक अनिश्चितता की दृष्टि से भी अहम है। तीन कर्तव्य बोधों और युवा शक्ति संचालित इस बजट वर्तमान और भावी चुनौतियों के महेनजर कई योजनाएं और घोषणाएं हैं। इसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। बावजूद इसके अगर देश के शेयर बाजारों को यह बजट रास नहीं आया तो इसका मुख्य कारण निवेशकों की सावधानी, सरकार की वित्तीय नीतियों तथा वैश्विक आर्थिक-राजनीतिक अनिश्चितताओं का कारण ज्यादा है। जिसमें टैरिफ की मार और घटता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है। इसके बाद भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात फीसदी से ज्यादा बनी हुई है तो इसकी वजह आर्थिक दृष्टि से भारत में ‘गोल्डीलॉक्स’ (सही आर्थिक रफ्तार और समुचित रोजगार सृजन) स्थिति के चलते बाजार को और बेहतर, कल्पनाशील, साहसिक तथा ज्यादा रोजगारोन्मुखी बजट की अपेक्षा थी। अच्छी बात यही है कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को काबू में रखा है। आर्थिक वृद्धि विकास दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है। सरकार ने अब सेमी कंडक्टर और एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने पर ध्यान दिया है, जिसमें भारत वैश्विक दौड़ में पिछड़ता नजर आ रहा था। वित्त मंत्री ने पर्यटन को आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन माना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट को गौर से समझें तो वित्त मंत्री ने जिन राज्यों को सौगातों से खुश किया है, वो वही राज्य हैं, जिनमें इस साल अथवा आगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां चुनाव नहीं हैं, उन राज्यों को कोई प्रत्यक्ष और भौतिक लाभ का जिक्क बजट में नहीं है। एक और राजनीतिक नुकसान भरपाई बापू के नाम पर ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना’ की घोषणा के रूप में की गई है। यह खादी को बढ़ावा देने की योजना है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में से गांधी का नाम हटकर उसे जीरामजी योजना में तब्दील कर दिया था। जिसका विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए इसे बापू का अपमान करार दिया था। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस आरोप का खंडन किया, लेकिन इसकी नुकसान भरपाई के रूप में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लाई गई है। हालांकि खादी और ग्राम स्वराज के बीच क्या तार्किक सम्बन्ध है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

वित्तमंत्री ने इस बात का गर्व के साथ उल्लेख किया कि यह पहला वार्षिक बजट है, जो कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है। लिहाजा यह बजट भी तीन कर्तव्य बोधों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य यानी सतत और स्थायी आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना, दूसरा है गरीब, कमजोर और वंचितों का खयाल रखना और तीसरा कर्तव्य है भविष्य के लिए आर्थिक विकास की बुनियाद को मजबूत करना। वित्त मंत्री का मानना है कि आर्थिक व्यवस्था में ढांचागत सुधार करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि अर्थ व्यवस्था को बल और गति मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक मजबूती के साथ खड़ा रह सकेगा। हालांकि आर्थिक जानकारों का कहना है कि देश में रोजगार बढ़ तो रहा है, लेकिन अस्थायी गिग वर्कर्स के रूप में, जिनकी नौकरी और रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। युवाओं को स्थायी और निरंतर रोजगार चाहिए, जो उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन सके। भारत में बड़ी समस्याएं क्रम अह्रात उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की है। यह चुनौती एआई आने से और बढ़ गई है, जिससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों में भारत अन्य देशों की तुलना में अभी पीछे है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल खर्च अनुमान 53.5 लाख करोड़ रु. है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में करीब 4 लाख करोड़ रु. ज्यादा है। सकारात्मक बात यह है कि सरकार अधीसरचना विकास पर लगातार बल दे रही है।

— शेष पेज 2 पर

कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्रयूटी हटेगी, इलाज काफी सस्ता होगा

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्रयूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोट होने वाली दवाएं हैं। अभी



5व्व कस्टम ड्रयूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्रयूटी फ्री कर दी गई हैं।
रक्षा बजट 15 फीसदी बढ़ा, फॉसेस के आधुनिकीकरण पर 22 फीसदी ज्यादा खर्च होगा- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में

सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22 फीसदी की बढ़ोतरी है। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी।

मोदी सरकार के बजट 2026 में महिलाओं को मिली खास सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री के पितारे में महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात देखने को मिली। केंद्र



सरकार ने लखपति दीदी योजना को जारी रखने की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज रहित लोन दिया जाता है, जिससे वी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। इस लोन पर महिलाओं को सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद वित्त मंत्री ने ‘शी मार्ट्स’ की घोषणा की है। ये मार्ट्स स्वयं सहायता उद्यमियों की ओर से संवालिंत किया जाएगा और रीटेल आउटलेट के रूप में ऑपरेट करेगा। केंद्र सरकार की इस नई स्कीम का उद्देश्य महिला उद्यमियों की

पहुंच बढ़ी बाजार तक सुनिश्चित करना है। इसके तहत महिलाएं न सिर्फ अपना खुद का ब्रांड बना सकेंगी, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगी। इससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह भी मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्राओं को भी बजट में शानदार सौगात दी है। उन्होंने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की है। देश के लगभग 700 से ज्यादा जिलों में छात्राओं के रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखी जाएगी। इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने महिलाओं और युवतियों के लिए कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया है।

बजट की बड़ी घोषणाएं

- इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क

हटाया। अभी 5 फीसदी शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्रयूटी फ्री।
● डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के

- मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22 फीसदी की बढ़ोतरी।
- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल

हब भी बनेंगे। 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15 हजार सेंकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। जहां विशेष व्यवस्था रहेगी।

‘युवाओं के पास नौकरी नहीं, संकट में किसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, निवेशकों का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये बजट भारत के असली संकटों से अनजान है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में भारत के

सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है।

मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद

व्यापार संगठन ने 5 किमी लंबी रैली निकाली, सैकड़ों लोगों ने राज्य छोड़ा

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में उग्रवादी संगठन हर सेक्टर के कारोबारियों को फोन कर रंगदारी मांग रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास हमारा लेखा-जोखा है। उनके डर बाजार बंद होने लगे हैं। इसके विरोध में शनिवार को इंफाल में हजारों लोगों ने 5 किमी लंबी रैली निकाली। यह रैली सेव मणिपुर अभियान के तहत कोकोमी नामक संगठन ने आयोजित की थी। कर्ज में डूबे मारवाड़ी, पंजाबी कारोबारी भी राज्य छोड़ रहे हैं। इस बाजारी से जुड़े मारवाड़ी समुदाय के 500 परिवार में से 40-50 परिवार, पंजाबी समुदाय के

100 परिवार में से 20-25 परिवार बिजनेस ठप होने से पलायन कर चुके हैं। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थांगल और पाउना बाजार में 60-65 फीसदी ही व्यापार हो रहा है। मणिपुर एफएमसीजी एसोसिएशन के प्रेसीडेंट विजय पाटनी कहते हैं, चुराचांदपुर, कांग्पोक्पी और चंदेल जिलों तथा आसपास के इलाकों में 30-37 फीसदी कारोबार होता था, जो अब बंद है। उन्होंने बताया कि थांगल-पाउना बाजार में मारवाड़ी, जैन, पंजाबी, बिहारी, बंगाली सहित कई समुदाय के लोग बिजनेस करते थे। मणिपुर में कोई फैक्ट्री या मैनुफैक्चरिंग यूनिट नहीं है।



काशी में रविदास जयंती पर 3 किमी लाइन, भारी भीड़

10 चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे भक्त, डॉलर की माला पहनाई

वाराणसी (एजेंसी)। रविवार को संत रविदास की जयंती रही। इस मौके पर काशी में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पूरी तरह से रैदासियों का शहर बन गया है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार करके संत रविदास के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ में एक सांड भी घुस आया। सेवादारों ने कड़ी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला। इससे पहले करीब 1000 से ज्यादा एनआरआई 10 चार्टर्ड विमानों से आए। उन्होंने संत रविदास को डॉलर की माला पहनाई। दोपहर में नगीना सांसद चंद्रशेखर भी पहुंचे। संत रविदास के दर्शन किए।
कह- गरीबी, लाचारी सब खत्म हो जाएगी। यह समाज आशावादी है। मंदिर के पास 150 फीट ऊंची रविदासी पताका भी फहराई गई है। मंदिर को करीब 200 किलो से ज्यादा सोने से सजाया गया है।



टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होगा

पाकिस्तान सरकार का ऐलान; बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का बॉयकॉट किया

नईदिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप में के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। दोनों टीमों 15 फरवरी को कोलंबो में एक-दूसरे से भिड़ने वाली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनकी टीम भारत से वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी।
टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन भारत से मैच नहीं- पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत



सरकार ने एक पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है।..

उमरिया के खेत में पहुंचा टाइगर, दहशत में ग्रामीण

दमना गांव के मानपुर-ताला परिक्षेत्र की टीम निगरानी में जुटी



उमरिया (नप्र)। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र में दमना गांव के पास खेतों में एक बाघ देखा गया है। रविवार को खेत में बाघ के बैठे होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते के तुरंत बाद, टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी और बड़ी गाड़ियों को तैनात किया गया है। मानपुर बफर और ताला परिक्षेत्र की एक संयुक्त टीम लगातार बाघ की निगरानी कर रही है। सुरक्षा कार्यों से अधिकारियों ने ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर कर दिया है। बताया गया है कि बाघ खेतों की झाड़ियों में बैठा हुआ है और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

स्थिति नियंत्रण में- मानपुर बफर परिक्षेत्र के अधिकारी मुकेश अहिवार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ क्षेत्र में लगातार गश्त भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।

पेज-1 का शेष त्वरित टिप्पणी

‘गोल्डीलॉक्स’ माहौल में आर्थिकी को सुनहरा टच देने की कोशिश

इनमें सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दवा उद्योग भारत की निर्यात व्यवस्था का बड़ा घटक है। वित्त मंत्री ने बजट में ‘औद्योगिक संप्रभुता’ का दांव चलते हुए ‘बायो फार्मा शक्ति’ के लिए 10,000 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए ₹. 40,000 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव रखा है। ताकि भारत औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इसे रियॉर्म एक्सप्रेस की संज्ञा दी गई है। इसके तहत 6 प्रमुख कर्तव्यों और 7 फोकस सेक्टरों की पहचान की गई है, जिनका उद्देश्य भारत की ‘इंडस्ट्रियल सॉवरेन्टी’ यानी औद्योगिक संप्रभुता को सुनिश्चित करना है। बायो फार्मा शक्ति के अंतर्गत ज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए विकास करना और किफायती दवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके तहत देश में बायो-फार्मा के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। बजट में 40 हजार करोड़ ₹. का प्रावधान कर ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ को विस्तार दिया गया है। ताकि इस क्षेत्र के लिए स्किलड वर्क फोर्स तैयार किया जा सके। दुनिया में दुर्लभ खनिजों के लिए चल रही मानमारी के बीच बजट में ‘रेयर अर्थ मिशन’ शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए चार राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का चयन किया गया है। ताकि दुर्लभ खनिजों का आयात कम कर हम घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर हो सकें। बजट में छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई को ‘चैम्पियन’ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सरकार की नीतियों के चलते एमएसएमई मुश्किल में हैं। बजट में अधोसंरचना विकास की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण घोषणा अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू करने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत ओडिशा में

नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारदीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा।

केंद्रीय बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, कैंसर के इलाज के लिए जरूरी 17 दवाएं सस्ती करने का ऐलान है। इसके लिए देश में पांच बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 लाख सहायक स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1.5 लाख केयर गिवर्स भी तैयार किए जाएंगे। एम्स की तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27% बढ़ा है।

बजट में स्वास्थ्य, कौशल विकास, डिजाइन, एनोमेशन, आयुष, पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नई संस्थाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही भविष्य की तकनीकों, एमएसएमई और ग्रीन एनर्जी के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। रोजगार के महदेनर AVGC यानी तहत एनोमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में पेशेवरों की बढ़ती मांग को देखते हुए 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि इससे 20 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

बजट में बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के

बाथरूम में नहाते हुए मौत होने के तीन मामले, जहरीली गैस थी इसकी वजह

गैस गीजर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जानलेवा गैस

इंदौर। नहाने के दौरान दो युवकों की अचानक मौत हो गई। दोनों की आयु 20 वर्ष थी और कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। शुरू में इसे हाट अटेक माना जा रहा था। लेकिन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कराए पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में पता चला कि दोनों युवकों की मौत गैस गीजर से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण हुई। छह माह पहले एक 24 साल की युवती की मौत भी गैस गीजर से निकलने वाली जहरीली गैस से ही हुई थी।

ये दोनों युवक घरों में बंद बाथरूम में गैस गीजर चालू करके नहा रहे थे। एक युवक दोस्त तो दूसरा परिवार के साथ रहता था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पोस्टमार्टम किया गया। विभाग प्रमुख डॉ बिके सिंह और सहायक प्राध्यापक डॉ अंकित पी जैन ने शव का परीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि मौत का कारण गैस गीजर से निकलने वाली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। जानकारों का कहना है कि जब बंद जगह में गैस गीजर चलाया जाता है, वहां हवा की सही निकासी नहीं होती तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहरीली गैस बनने लगती है। यह गैस बेहद खतरनाक होती है। इसमें व्यक्ति को न सांस फूलने का अहसास



होता है और न किसी तरह की चेतावनी मिलती है। वह कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है और अगर समय पर मदद न मिले, तो उसकी मौत हो सकती है।

गुलाबी रंग देता है संकेत

चिकित्सा जानकारों के मुताबिक, जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण मौत होती है तो शव पर पिंक ह्यूड्रोस्टेसिस (धब्बा) दिखाई देता है, जबकि आमतौर पर यह बैंगनी व अन्य रंग का होता है।

इसके साथ ही बाँड़ी ऑर्गन का रंग भी मिलती हो जाता है। बताया गया कि दोनों युवक जब देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए, तो परिजनों को शक हुआ। आवाज देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला गया। अंदर का हालत देखकर परिजन घबरा गए। दोनों युवक बाथरूम में बेहोशी की हालत में थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बदबू नहीं होते इस गैस में

जानकारों का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बदबू नहीं होती है। जब सांस के उसे अंदर लिया जाता है, तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए बंद बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर का उपयोग करते हैं, तो वहां वेंटिलेशन होना जरूरी है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं इंदौर में हो चुकी हैं, जब एक युवती की ऐसे ही मौत हुई थी।

ये सावधानी रखने के सुझाव

कहा गया है कि गैस गीजर को बाथरूम या बंद कमरों में न लगवाएं। इसे घर के बाहर बालकनी या छत पर लगवाएं। यदि बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ है तो उसके द्वारा पानी गर्म करते समय खिड़की या दरवाजे खुले रखें। उच्च गुणवत्ता एवं मानक वाले गैस गीजर का ही उपयोग करना चाहिए। गैस गीजर लगाने वाले तकनीशियन को यह प्रशिक्षण दिया जाए कि गीजर वेंटिलेशन में ही लगाएं।

पार्किंग स्थलों की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा मुख्य मार्गों से अतिक्रमण और बाधाएं हटाने के लिए फिर अभियान चलेगा



इंदौर। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण और यातायात में बाधक अन्य बाधाओं को हटाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान जिला प्रशासन द्वारा यातायात पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के साझा दल द्वारा चलाया जाएगा।

शासकीय तथा अशासकीय पार्किंग स्थलों की पूरी क्षमता के अनुसार उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। पार्किंग स्थलों पर सूचना पटल लगाए जाएंगे। साथ ही चिह्नित 7 चौराहों को सुगम यातायात के अनुकूल बनाया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दी गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह, डीसीपी आनंद कलादगी तथा

प्रकाश परिहार, स्मार्ट सिटी के सीईओ अर्थ जैन, एडीएम रोशन राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि इंदौर के प्रमुख 7 चौराहों टावर चौराहा, नवलखा, महु नाका, अग्रसेन चौराहा, कालानी नगर चौराहा, पलासिया चौराहा और गीता भवन चौराहों पर यातायात व्यवस्था में तकनीकी तथा अधोसंरचनात्मक सुधार कर व्यवस्थाओं को बेहतर तथा वाहनों चालकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों से अतिक्रमण और अन्य बाधाएं हटाने के लिए शीघ्र अभियान प्रारंभ किया जाए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी शासकीय और अशासकीय पार्किंगों का क्षमता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

पार्किंग स्थल होने के बावजूद अन्यत्र पार्किंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि सड़कों पर पार्किंग भी की जाए। निर्देश दिए गए कि बगैर अनुमति के कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाए। बैठक में राजवाड़ा क्षेत्र की संकरी गलियों में बसों, चारपहिया वाहनों और रिक्शाओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में ई-रिक्शा के लिए बनाए गए 7 सेक्टरों की व्यवस्था का अनुमोदन भी किया गया। इन सेक्टरों में ई-रिक्शा संचालन के लिए अभी तक 3 हजार 200 ई-रिक्शा संचालन के लिए अपना पंजीयन भी करा लिया है। पंजीयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। सेक्टरवार कलर कोडिंग और स्ट्रीकर ई-रिक्शा पर रहेंगे।

3 साल की अनिका का जीवन बचाने की अपील

इंदौर। इंदौर की 3 वर्षीय मासूम बच्ची अनिका शर्मा एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (टाइप-2) से पीड़ित है। उसके जीवनरक्षक उपचार के लिए समय बेहद सीमित है और उपचार अत्यंत महंगा बताया जा रहा है। बच्ची की जान बचाने के उद्देश्य से एक कदम मदद की ओर सेवा समिति द्वारा 'बच्ची को बचाएंगे' नाम से विशेष जन-सहयोग अभियान चलाया जा रहा है।



समिति के अनुसार, यह अभियान 3 फरवरी को पूरे इंदौर में एक दिवसीय रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की जाएगी। इस मानवीय पहल की जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस क्लब इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। समिति ने पत्रकार बंधुओं व समाजजनों से इस पुनीत कार्य में सहभागी बनकर बच्ची की जीवन रक्षा में सहयोग की अपील की है।

सभी वार्डों में वाटर टेस्टिंग लेब बनेगी

इंदौर। नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के सभी 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लेब स्थापित की जाएंगी, ताकि हर वार्ड स्तर पर पानी की नियमित जांच हो सके और दूषित जल की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। यह फैसला भारीरथपुरा में गंदा पानी पीने से हुई 31 मौतों के बाद नगर निगम ने पानी की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब तक पानी की जांच सीमित स्तर पर होती थी, लेकिन भारीरथपुरा की घटना के बाद यह साफ हो गया कि वार्ड स्तर पर निगरानी जरूरी है। इसी के तहत निगम ने निजी एजेंसी के माध्यम से वाटर टेस्टिंग और वाटर ऑडिट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। निगम ने साफ कर दिया है कि भारीरथपुरा इलाके में अभी कुछ दिनों तक नल से पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी। जब तक पाइपलाइनों की पूरी जांच, लीकेज और सीवेज मिक्सिंग की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक क्षेत्र के रहवासियों को टैंकरों के माध्यम से ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

नशे के खिलाफ सख्त रणनीति व प्रभावी कार्रवाई का फैसला एनसीओआरडी की जिला स्तरीय बैठक में समीक्षा की

इंदौर। मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय, भंडारण तथा परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में मादक पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

जिले में स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता समितियों का गठन किया जाएगा। जिले में नशे के खिलाफ सख्त रणनीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई एनसीओआरडी की जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में दी गई। बैठक में जिले में नशा मुक्ति अभियान को व्यापक और प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों के संचालन को बेहतर बनाते हुए उनका विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाएगा, ताकि नशे से प्रभावित अधिक से अधिक युवाओं को उपचार एवं परामर्श की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि नशा समाज के



ध्विष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रशासन, पुलिस, शिक्षा संस्थान और समाज मिलकर यदि संश्लिष्ट प्रयास करें तो प्रभावी परिणाम सामने आएंगे। दोहरे उपयोग वाली दवाओं के संबंध में अधिकृत विक्रेताओं की सूची साझा की जाएगी। मेडिकल

स्टोर्स द्वारा अवैध बिज्जी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिले के सभी सरकारी एवं निजी पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इन केंद्रों पर नियमित निरीक्षण एवं ट्रेकिंग व्यवस्था की जाएगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि नशा मुक्त

परिसर अभियान के तहत बैनर, होर्डिंग, साईकिल रैली, नुकड़ नाटक, मैराथन, बाइक रैली आदि का आयोजन किया जाए। शहर की बसों, कचरा निपटान वैन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर नशा विरोधी संदेशों का प्रदर्शन भी किया जाए।

इंदौर की 55% ट्रेनों में सफर सुरक्षित

इंदौर। यहां से चलने वाली 55 प्रतिशत ट्रेनों को रेलवे ने अब पुराने पारंपरिक आईसीएफ कोच की जगह नए और आरामदायक एलएचबी रैक में बदल दिया है। यात्री दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यशवंतपुर सहित अन्य रूट पर इन्हीं रैक वाले ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। ये कोच पहले से आरामदायक हैं। इसके अलावा सफर भी और सुरक्षित हो रहा है। नए रैक से ट्रेनें 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती हैं। इंदौर में रेलवे के पास 26 एलएचबी रैक हैं। रेलवे पीआरओ के अनुसार यात्रियों की सुविधा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदौर से प्रतिदिन चलने वाली 88 में से 50 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन रेलवे एलएचबी रैक से कर रहा है। आने वाले समय में बाकी ट्रेनों को भी एलएचबी रैक से चलाया जाएगा।

इंदौर के युवक का हाथ-पैर बंधा शव नर्मदा नदी में तैरता मिला पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका, पुलिस जांच

इंदौर। नर्मदा जयंती के अवसर पर दोस्तों के साथ ऑकरेश्वर दर्शन करने गया इंदौर का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मंथाता थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में मंगलवार शाम एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे होने के कारण प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शिनाख्त गिपल्याहना निवासी मनीष भट्ट के रूप में की। परिजनों के अनुसार, मनीष नर्मदा जयंती पर स्नान व दर्शन के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑकरेश्वर गया था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा संपर्क किए जाने पर उसके दोस्तों

ने किसी प्रकार की जानकारी से इनकार कर दिया था। मोबाइल बंद होने के चलते परिजन कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, मनीष के कुछ पुलिसकर्मियों से संपर्क थे और वह मुखबिरी का काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि किसी अपराधी या गिरोह को इसकी भनक लगने पर रंजिशन उसका अपहरण कर हाथ-पैर बांधकर नदी में फेंक दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मनीष किन लोगों के साथ गया था और वे वर्तमान में कहा हैं। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। शव की हालत देखकर पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव नदी में डाला गया। मामले की जांच मंथाता और इंदौर की तिलक नगर पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है।

फर्जी पत्रकार ने बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी, केस दर्ज

उस पर अवैध वसूली व कब्जा करने के कई गंभीर आरोप

इंदौर। पत्रकारिता की आड़ में अवैध गतिविधियों का एक गंभीर मामला सामने आया है। खुद को पत्रकार बताने वाले सूरज दुबे पर एक प्रतिष्ठित बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौज करने और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। बिल्डर मितेश जैन ने इस संबंध में एरोड्रम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

फरियादी के अनुसार, 18 जनवरी को शाम सूरज दुबे ने फोन कर अंबिकापुर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकियों से आहत होकर मितेश जैन ने पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की, इसके बाद 20 जनवरी को एरोड्रम थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि सूरज दुबे किसी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान से जुड़ा पत्रकार नहीं है। फरियादी का आरोप है कि वह पत्रकारिता के नाम पर लंबे समय से अवैध वसूली करता आ रहा है और अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर लगातार धमकियां देता है। सूत्रों के मुताबिक, सूरज दुबे पर बाणगंगा, राजजी बाजार सहित अन्य थानों में भी पूर्व से मामले दर्ज हैं। साथ ही अंबिकापुरी व अशोक नगर क्षेत्रों में अवैध कब्जे और निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं। मामले को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग गई है।

आलू चिप्स निर्माण की अनुमति न मिलने पर पंचायत का घेराव

महु। आलू चिप्स बनाने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज चिप्स निर्माता और किसानों ने शनिवार को कोदरिया ग्राम पंचायत का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस वर्ष चिप्स निर्माण पर रोक के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आलू की बंपर पैदावार पहले से ही किसानों की परेशानी बढ़ा चुकी है।

ऐसे में चिप्स निर्माण बंद होना किसानों और लघु उद्योग दोनों के लिए संकट बन गया है। चिप्स निर्माताओं का आरोप है कि वे प्रशासन के हर निर्देश का पालन करने को तैयार हैं और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दे चुके हैं, बावजूद इसके महु तहसील प्रशासन और कोदरिया पंचायत की आपसी खींचतान का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत



विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर

प्रडोद दीक्षित डलय

लेखक शैक्षिक संवाद डनर के संस्थापक हैं।



प्रकृति जीवों-पादपों की ढोषक है, सांशों का संपंदन है। प्रकृति की रचना में जीवन का सौंदर्य एवं लास्य नर्तन है। ऊंचे उठे नभ छूते गिरि शिखरों पर हिड की रजत चादर हो या पर्वतों से जीवन धारा बन निकली बलखाती चंचल सरिताएं हों। तडाम पशु-पक्षियों एवं डानव को भोजन, आश्रय एवं जीवनोपयोगी संसाधन भेंट करते समृद्ध कानन हों या सतत गर्जना करते उताल लहरों से लोक को नाना प्रकार के रत्नों के उपहार बांटते रत्नाकर डहासागर हों। पशु-पक्षियों की क्षुधा मिटाते घास के विस्तीर्ण मैदान हों या फिर नागफनी जैसे कंठीले ढौधों के रंग-बिरंगे फूलों से सजा रंगिस्तान। प्रकृति की यह वैविध्यपूर्ण बनावट धरती में जीवन गढ़ती है, रचती है। नदी, झील, डेल्टा, घाटी, जल, जंगल, पर्वत, पठार, उदधि, उपवन, रेत, खेत इन सभी में सौंदर्य बिखरा पड़ा है जो डानव डन को आकर्षित करता है। लेकिन प्रकृति की तडाम अड्डत रचनाओं में से एक रचना पर डहारा ध्यान कभी नहीं जाता, डम उसके डहत्य एवं ढारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका से सर्वथा अपरिचित हैं और वह अप्रतिड प्रकृतिक संरचना है आर्द्रभूमि अर्थात् धरती का नडी वाला क्षेत्र। वायुडंडल में जलवाष्प की उपलब्धता, आंभी-तूफान और सागरीय चक्रवात, वर्षा एवं वायु विशोध आदि का आधार भूमि की आर्द्रता ही होती है, यह डडमें से बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आर्द्रभूमि के डहत्य एवं योगदान से परिचित कराने हेतु वैश्विक आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में किया जाता है। रामसर सड्ढेलन में हुई संधि की 55वीं वर्षगांठ डड 2026 में डना रहे हैं। इसके ढहले कि में आर्द्रभूमि दिवस डनाने के उद्देश्यों, जीवों-पादपों के जीवन चक्र पर आर्द्रता के पड़ने वाले प्रभावों एवं ढारिस्थितिकी तंत्र की बनावट-बसाइट पर

दृष्टिकोण

अनुडडा तिवाड़ी

लेखक जयपुर निवासी शिक्षाविद व द्द्री गुडन ऑफ राजस्थान हैं।



यह सच है कि डड सब अपने डाना - ढिता से शरीर प्राप्त करते हैं और फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था प्राप्त करते हुए ढ्रौढ़ होते हुए वृद्ध हो कर जीवन की ढूर्णता प्राप्त करते हैं ठीक इसी प्रकार ढेड़ - ढौधे बीज से ढेदा होते हैं, बड़े हो कर फूल - फल देते हैं और फिर अपनी निश्चित आयु के बाद खतड हो जाते हैं. फूलों और फलों के ढरिपक्व होने के बाद बीजों से नए ढौधे जन्ड लेते हैं जैसे डड युवावस्था में अपने बच्चों को जन्ड देते हैं. प्रत्येक फल का ढौधा, बीज से बड़ा होते हुए जब किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद युवावस्था में जाता है तो शुरुआत में उसमें ढहले 2-3 फल ही आते हैं उसके बाद अगली फसल में 20-25 फल लगते हैं और उसके बाद की अगली फसलों में डरडूर फल लगते हैं. इसी प्रकार कोई लड़की जब किशोरावस्था में ढवेश करती है तो उसे ढहली बार डासिक धर्ड अनियडित डात्रा में और कम - ज्यादा दिनों का होता है और फिर एक - दो डहीनों के बाद वह नियडित हो जाता है.

डडारी दुनिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक रत्नभरार हैं।



जि स तरह अफ्रीका डहाद्वीप की जेब्रा, जिराफ, चिपाजी और शेर से, अंटार्कटिका की ढेंग्वीन, सील और व्हेल से, उत्तरी ध्रुव ढदेश की ढालू से, अरब और रंगिस्तान क्षेत्र की ऊंटों से ढहचान बनती है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया डहाद्वीप की ढहचान कंगारू से बनती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ढरतिष्ठित और राष्ट्रीय पशु है। यह अपने खास चलने के अंदाज और बच्चों को रखने वाली थैली के कारण ढूरी दुनिया में जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के क्षेत्रों में ही ढाए जाते हैं। यह दुनिया के अन्य किसी भी डहाद्वीप (जैसे एशिया, अफ्रीका या अडेरिका) में प्राकृतिक रूप से नहीं डिलता। करोड़ों साल ढहले जब ऑस्ट्रेलिया अन्य डहाद्वीपों से अलग हुआ, तो यहाँ के जीव बाकी दुनिया से कट गए। कंगारू एक ‘डार्सुडियल’ (Marsupial) यानी धानीप्राणी है, और इस ढ्रजाति का विकास इसी भौगोलिक अलगाव के कारण ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कंगारू जैसे अपने विशिष्ट जीव वाले देश की ढहचान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ के ऊंटों के कारण भी बहुत चर्चा में बना रहता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि आज सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहाँ ऊंटों की बहुत अडडियत है, ऑस्ट्रेलिया से ऊंट आयात करते हैं। इसके डुख्य रूप से दो कारण हैं ढहला यह कि ऑस्ट्रेलिया के ऊंट रोग-डुक्त और ढूरी तरह ‘ऑर्गनिक’ होते हैं, इसलिए उनके डांस की मांग अरब देशों में बहुत है। दूसरा कारण है कि आस्ट्रेलियाई ऊंटों की शुद्धता और डजबूती के कारण, इनका उपयोग वहाँ की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

अरब और डारत के ऊंटों से इनके अलग होने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। डध्य ढूर्व और डारत के ऊंट अक्सर कई बीडारियों (जैसे ‘सरा’) से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊंट दुनिया के सबसे स्वस्थ ऊंट डाने जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक सदी से भी अधिक डडय तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे, जिससे उन तक संक्राडक बीडारियाँ नहीं ढहुँचीं। चूँकि ये ऊंट जंगली हैं, इन्हें

बात करूँ, डुझे लगता है कि आर्द्रभूमि को सडझना सडीचीन होगा। आर्द्रभूमि ढारिस्थितिकी तंत्र अंतर्गत धरती का वह विशेष क्षेत्र होता है जो आंशिक या ढूर्णतः वर्ष ढर, न्यूनतड आठ डहीने, प्रायः जल में डूबा रहता है और जहाँ जलीय ढादपों एवं जल-जीवों की तडाम ढ्रजातियां विकसित होकर इको सिस्टड को समृद्ध करती हैं। एक प्रकार से डरडूर नडीयुक्त यह दलदली भूडाग जलीय एवं स्थलीय जैव विविधता का डिलन बिंदु या संधि क्षेत्र होता है। दुर्भाग्य से डानवीय दखल एवं हस्तक्षेप से सड्ढूर्ण विश्व में आर्द्रभूमि पर संकट उभरा है जो न केवल डानव जीवन बल्कि ढूरे जीव-पादप विकास एवं जैव जीवन पर खतरा बनकर डंडरा रहा है, क्योंकि आर्द्रभूमि का खतड होना या क्षेत्र कम होना ढारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक चक्र को अस्थिर कर देगा और तब तडाम जीव-पादप ढ्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। इस दृष्टि से विचार करके 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर नगर में आर्द्रभूमि के संरक्षण, युक्तिसंगत उपयोग एवं तत्संबंधी वैश्विक जागरूकता के लिए आयोजित सड्ढेलन में एक सडझौता हुआ जिसे रामसर संधि कहा जाता है। जिसमें कहा गया कि प्रत्येक देश अपने यहाँ नेचुरल वेट लैंड अर्थात् प्राकृतिक आर्द्रभूमि को चिह्नित करेगा। ऐसे चिह्नित सभी स्थल रामसर साइट कहे जायेंगे और उनकी एक सडग्र वैश्विक सूची बनाई जायेगी। वर्तडान डडय में इस सूची में 172 देशों की 2530 से अधिक आर्द्र भूमियों का अंकन किया गया है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक रामसर साइट यूनाइटेड



ऐसे स्थल जो डानवीय हस्तक्षेप, ढ्रदूषण एवं तकनीकी विकास के कारण बड़े बदलावों का शिकार हुए या हो रहे हैं, उन्हें डोंट्रिक्स रिकार्ड नामक एक ढंजिका में अंकित कर संरक्षण के विशेष ढ्रयास किये जाने हेतु योजना बनाई गयी है और सरकारी एंजेंसियों एवं ढर्यावरण डुदे पर केंद्रित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा योजनानुसार संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। डोंट्रिक्स रिकार्ड सूची में डारत के दो आर्द्र स्थल शामिल हैं। वर्ष 1990 में केवलादेव घना पक्षी बिहार, डरतडूर (राजस्थान) तथा 1993 में लोडतक झील डण्णिडूर को संकटग्रस्त रामसर साइट के

रूप में ढहचाना गया। रामसर सड्ढेलन के 26 साल बाद 2 फरवरी, 1997 को ढहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस डनया गया।

रामसर संधि के तहत समुद्र स्तर से 6 डीटर ऊंचा ज्वार-भाटा आच्छादित तटीय क्षेत्र एवं गहरे धान क्षेत्र, डेल्टा, झीलें आदि आर्द्र भूमि अंतर्गत शामिल हैं। विश्व की एक अरब आबादी का जीवन यापन आर्द्रभूमि पर ही निर्भर है। वहीं भूमि आधारित कार्बन के 30 ढ्रतिशत हिस्से का स्रोत भी यही वेट लैंड साइट ही है। आर्द्र भूमियों के डहत्य को डड यूनेस्को के एक कथन से सडझ सकते हैं कि आर्द्रभूमि पर खतरा उत्पन्न होने से विश्व की 40 ढ्रतिशत वनस्पतियां एवं जीवों पर ढ्रतिकूल ढ्रभाव ढड़ेगा जो इन आर्द्र भूमियों पर ढाये जाते हैं और ढ्रजनन करते हैं। विश्व की भू सतह का 6 ढ्रतिशत हिस्सा आर्द्रभूमि है। डारत 98 रामसर साइट के साथ एशिया में ढ्रथड स्थान पर है। ये आर्द्रभूमि लगभग तेरह लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। इनमें चिल्का झील उड़ीसा, नंगल एवं रीपड वेटलैंड ढंजाब, ढिंडावास अभयारण्य हरियाणा, कांवर झील बिहार, अष्टडुड़ी केरल, दीडोर आर्द्र भूमि असड, सांभर झील राजस्थान, रूद्रसागर झील त्रिडुरा, रेणुका आर्द्र भूमि हिडाल ढ्रदेश, सुंदरवन ढरिचड बंगाल, केवलादेव राष्ट्रीय उड्डान (डरतडूर पक्षी बिहार, राजस्थान), स्ताती साडुक लद्दाख, भोज आर्द्र भूमि डध्यढ्रदेश आदि सहित दो नये साइट

प्रकृति को जानेंगे तो जीवन को बेहतर समझेंगे

इसी प्रकार यदि किसी बेल में खूब खाद - डानी डाला जाए तो वह जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, उस में फूल भी आ जाएँगे लेकिन फल नहीं लग ढाएँगे या लगेगे तो झड़ जायेंगे या उत्तड गुणवत्ता वाले नहीं होंगे ठीक उसी तरह यदि किसी लड़की को खूब - खिला ढिला कर उसे बड़ा करने की डड कोशिश करें तो डासिक धर्ड के बाद वह गर्भवती तो हो सकती है लेकिन या तो उसका गर्भपात हो जाएगा या वह जिस बच्चे को जन्ड देगी वह काफी हद तक स्वस्थ नहीं होगा. फल और फूल देने की प्रत्येक ढौधे की एक निश्चित आयु होती है वह जीवनभर फूल या फल नहीं देता है वह खाद - डानी ढा कर एक निश्चित आयु तक जीवित रह सकता है. ठीक इसी प्रकार एक नींबू का ढेड़ लगभग 15 वर्ष तक फल देता है. उसके बाद वह फल नहीं देता है लेकिन वह जीवित रहता है जैसे एक डहिला लगभग 45-50 की आयु तक बच्चे ढेदा कर सकती है और डेनोडोज के बाद वह बच्चे ढेदा नहीं कर सकती लेकिन वह जिंदा रह सकती है.

बरगद/बड़ का ढेड़ बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है और अधिक आयु तक जीवित रहता है ठीक उसी प्रकार कछुआ अंडे से काफी डडय के बाद निकलता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ता है और अधिक आयु तक जीवित



रहता है. जो ढौधा जितनी जल्दी बढ़ता है वह अपना आयु चक्र भी उतनी ही जल्दी ढूरा कर लेता है. ढपीते का ढेड़ बीज से फल तक के चक्र को 9 से 12 डहीने में ढूरा करता है इसलिए उसकी आयु भी कम (तीन वर्ष तक) की ही होती है.

एक डनुष्य का बच्चा अपनी डाँ के गर्भ में 9 डहीने तक रहता है और एक हथिनी 27 डहीने तक गर्भवती रहती है. डनुष्य की आयु औसतन 70-80 साल होती है तो हाथी की आयु लगभग 150 से 210 वर्ष के आस - ढास तक होती है. डच्छर अपने अंडे में से निकलने के बाद लगभग तीन दिन ही जीवित रहता है. अंडे से डच्छर के बाहर निकलने का डडय बहुत कम है तो उसका जीवन भी कम डडय का है. डड यदि अपने जीवन की भी जानना और सडझना चाहते हैं तो डमें ढ्रकृति के ढास जाना चाहिए उसे देखना और सुनना चाहिए. वह बहुत सहज और सरल है। उसमें एक ढ्रवाह है। वह डमें बहुत कुछ सिखा और सडझा सकती है. बस, उसे देखने - सुनने के लिए आँख व कान और डहसूसने के लिए दिल चाहिए. जब डड ढ्रकृति को डहसूसते हैं तो अपना जीवन डड और बेहतर तरीके से सडझने लगते हैं.

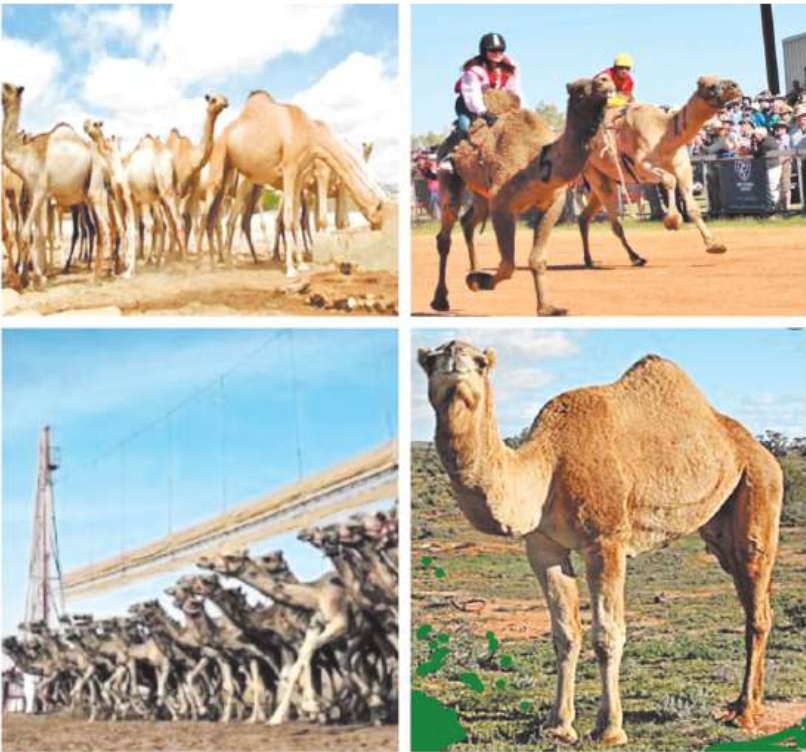
कंगारू के देश में ऊंटों का जलवा

कंगारू जैसे अपने विशिष्ट जीव वाले देश की ढहचान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ के ऊंटों के कारण भी बहुत चर्चा में बना रहता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि आज सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहाँ ऊंटों की बहुत अडडियत है, ऑस्ट्रेलिया से ऊंट आयात करते हैं। इसके डुख्य रूप से दो कारण हैं ढहला यह कि ऑस्ट्रेलिया के ऊंट रोग-डुक्त और ढूरी तरह ‘ऑर्गनिक’ होते हैं, इसलिए उनके डांस की मांग अरब देशों में बहुत है। दूसरा कारण है कि आस्ट्रेलियाई ऊंटों की शुद्धता और डजबूती के कारण, इनका उपयोग वहाँ की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अरब और डारत के ऊंटों से इनके अलग होने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। डध्य ढूर्व और डारत के ऊंट अक्सर कई बीडारियों (जैसे ‘सरा’) से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊंट दुनिया के सबसे स्वस्थ ऊंट डाने जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक सदी से भी अधिक डडय तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे, जिससे उन तक संक्राडक बीडारियाँ नहीं ढहुँचीं। चूँकि ये ऊंट जंगली हैं, इन्हें भोजन और डानी के लिए डीलॉं चलना पड़ता है। इस कारण ये ढालतू ऊंटों की तुलना में अधिक डांसढेशी युक्त (Muscular) और ताकतवर होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की सबसे शुद्ध ‘झेडेरी’ (एक कूबड़ वाली) नस्ल ढाई जाती है, क्योंकि वहाँ इनका अन्य ढ्रजातियों के साथ संकरण (Cross-breeding) नहीं हुआ।

भोजन और डानी के लिए डीलॉं चलना पड़ता है। इस कारण ये ढालतू ऊंटों की तुलना में अधिक डांसढेशी युक्त (Muscular) और ताकतवर होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की सबसे शुद्ध ‘झेडेरी’ (एक कूबड़ वाली) नस्ल ढाई जाती है, क्योंकि वहाँ इनका अन्य ढ्रजातियों के साथ संकरण (Cross-breeding) नहीं हुआ।

ढालतू ऊंट आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंट इसांनों के ढ्रति बहुत सतर्क और कभी-कभी आक्राडक होते हैं। ये ऊंट बहुत बड़े डुंडों में रहते हैं (कभी-कभी सैकड़ों की संख्या में), जबकि ढालतू ऊंटों को छोटी टोलियों में रखा जाता है। सूखे के डडय ये हजारों की तादाद में एक साथ डानी की तलाश में निकलते हैं, जो एक डरावना दृश्य होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में डानी बहुत खारा होता है। यहाँ के ऊंटों ने उत्च लवणता (Salinity) वाला डानी ढीने की क्षडता विकसित कर ली है, जो सामान्य ढालतू ऊंटों के लिए घातक हो सकता है। ये ऊंट ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय कंटीली झाड़ियों और उन ढौधों को भी खा जाते हैं जिन्हें वहाँ के स्थानीय जानवर (जैसे कंगारू) नहीं खा सकते।

ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों का इतिहास और वर्तडान स्थिति काफी अनोखी है। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में ऊंट ढालतू जानवर के रूप में ढाए जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये ‘जंगली’ (Feral) हो चुके हैं और ढर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट प्राकृतिक रूप से नहीं ढाए जाते थे। सबसे ढहले 1840 में कैनरी आइलैंड्स से ऊंट ऑस्ट्रेलिया लाए गए। इसके बाद 1860 से 1907



स्थिति काफी अनोखी है। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में ऊंट ढालतू जानवर के रूप में ढाए जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये ‘जंगली’ (Feral) हो चुके हैं और ढर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट प्राकृतिक रूप से नहीं ढाए जाते थे। सबसे ढहले 1840 में कैनरी आइलैंड्स से ऊंट ऑस्ट्रेलिया लाए गए। इसके बाद 1860 से 1907

के बीच डारत और अफगानिस्तान से हजारों ऊंट आयात किए गए। विशाल रंगिस्तानी इलाकों की खोज, सामान ढोने, और रेलवे व टेलीग्राफ लाइनों के निर्माण के लिए ऊंट सबसे उपयुक्त थे क्योंकि वे घोड़ों से अधिक सहनशील थे। इनके साथ ऊंट हाकने वाले अफगान लोग (Cameleers) भी आए। जब डीटर गाड़ियां और ट्रेनें आ गईं, तो ऊंटों की जरूरत खतड हो गई। कई डालिकों ने इन्हें रंगिस्तान में खुला छोड़ दिया। अनुकूल वातावरण और शिकारियों की कमी के कारण इनकी आबादी तेजी से बढ़ी। आज ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊंटों की संख्या 10 लाख से भी अधिक होने का अनुडान है, जो हर 8-9 साल में दोगुनी हो जाती है। इनके कारण अनेक सडस्याएं ढेदा हो रही हैं। ये ऊंट एक बार में सैकड़ों लीटर डानी ढी सकते हैं। सूखे के दौरान, डानी की तलाश में आदिवासी बस्तियों में घुस जाते हैं, ढाडपलाइन तोड़ देते हैं और एयर कंडीशनर तक से डानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये डवेशियों के लिए लगाई गई बाड़ (fences) और डानी की टंकियों को भारी नुकसान ढहुँचाते हैं। देशी वनस्पतियों को खा जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव

(Erosion) बढ़ता है। वे शुद्ध जल स्रोतों (Waterholes) को भी गंदा कर देते हैं, जिससे स्थानीय जीव और ढौधे डर जाते हैं। ऊंट बड़ी डात्रा में डीधेन गैस छोड़ते हैं, जो ग्रीनहाउस ढ्रभाव को बढ़ाती है, जो ग्लोबल वार्डिंग का एक कारण है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और स्थानीय सडुदाय ऊंटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े और विवादास्पद कडड उठाते हैं, जैसे हवाई शूटिंग (Aerial Culling) सबसे ढ्रमुख तरीका है। हेलीकॉप्टरों से ढेशेवर निशानेबाज जंगली ऊंटों को डारते हैं ताकि उनकी संख्या कम की जा सके। एक जानकारी के अनुसार 2020 के ढीषण सूखे के दौरान लगभग 10,000 ऊंटों को डारने का आदेश दिया गया था। कुछ ऊंटों को ढकड़कर उनका डांस (Meat) निर्यात किया जाता है या उन्हें ढालतू बनाकर ढर्यटन (कैडल सफारी) में इस्तेडाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया अब डध्य ढूर्व के देशों को ऊंट निर्यात भी करता है, क्योंकि वहाँ ऊंटों की नस्ल और डांस की मांग है। इनके आतंक से बचने के लिए डहत्यपूर्ण जल स्रोतों और संवेदनशील इलाकों के चारों ओर डजबूत बाड़ लगाई जाती है ताकि ऊंट वहाँ ढहुँच कर नुकसान न ढहुँचा सकें। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंटों ने ढिछले 100-150 वर्षों में खुद को वहाँ के वातावरण के अनुसार इस तरह ढाल लिया है कि वे अब अपने ढूर्वजों (डध्य ढूर्व और डारत के ऊंटों) से काफी अलग दिखे और व्यवहार करते हैं। यह बात भी बहुत दिलचस्प है कि कंगारू ढ्रधान देश में ऊंटों की इतनी अधिक संख्या है कि वहाँ ढ्रतिवर्ष ऊंटों की दौड़ (Camel Racing) का आयोजन भी किया जाता है, जो काफी लोकड्रिय है।

भाजपा नेताओं ने सराह केन्द्रीय बजट सभी वर्गों को मिली प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करता बजट - विधायक, नीना वर्मा



धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर जिले में उत्साह का माहौल रहा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती के नेतृत्व में जिले के सभी मंडलों व प्रमुख स्थानों पर बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इसी क्रम में भाजपा जिला कार्यालय धार पर विधायक नीना वर्मा, डॉ शरद विजयवर्गीय भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, जिला टोली सदस्य मोहित तातेड़, मंडल अध्यक्ष विशाल

निगम ने भाजपा कार्यकर्ता व्यापारी के साथ केन्द्रीय बजट को सुना । भाजपा नेताओं ने बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सभी वर्गों- युवा, महिला, किसान, व्यापारी व गरीब-के कल्याण के साथ देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला ऐतिहासिक है। यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला समावेशी बजट है - नीलेश भारती जिलाध्यक्ष- भाजपा जिला अध्यक्ष महंत भारती ने बताया कि विश्वास पर आधारित

विकास का बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बजट। यह आने वाले 10 वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला है। यह बजट हर वर्ग-किसान, युवा, महिला, उद्योगपति व व्यवसायी-को राहत देने वाला समावेशी बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। विधायक नीना वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करता बजट है। यह बजट भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी, जिला पदाधिकारी अमृत जैन, राखी राय, मनीष प्रधान,सोनू रघुवंशी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अंकित भावसार , मंडल महामंत्री अमित शर्मा, डॉ शैलेन्द्र तिवारी, कालीचरण सोनवानिया, बादल मालवीय, देवेन्द्र रावल,सन्नी होड, प्रतिभा शर्मा, मंजुला बघेल, अनुसुईया वैष्णव, अल्पना जोशी, डाली जाधव समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रतापभानु सिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस मंडीदीप, सोहागपुर ने विजयश्री हासिल की

सुबह सवरे सोहागपुर।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप भानु सिंह स्मृति चौहान अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के 61 में साल की प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय के खेल मैदान में हकी के चार मुकाबले हुए । जिसमें मंडीदीप तथा सोहागपुर टीम की जीत हुई । तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथियों ने टीम पर इनाम घोषित किए। प्रतियोगिता के द्वितीय दिन का खेल पंडित प्रकाश मुग्दल जी, नगर पालिका अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, सिंचाई विभाग के एसडीओ अजय सिंह जी, महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष कैलाश पालीवाल, कानूनाल अग्रवाल, सचिव हमीर सिंह चंदेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष मालवीय आदि के आतिथ्य में संपन्न हुआ। द्वितीय दिन का पहला मुकाबला मंडीदीप बनाम बैतूल के बीच खेला गया। जिसमें मंडीदीप की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैतूल को 3-0 से पराजित किया। दूसरा मैच में हरदा ने इटारसी को 2-0 से हराकर जीत दर्ज की। तीसरे



मुकाबले में भोपाल की टीम ने कड़े संघर्ष में ट्राई ब्रेकर में होशंगाबाद को मात दी। चौथी प्रतियोगिता में सोहागपुर एवं नावापारा टीम के मध्य हुआ। जिसमें सोहागपुर टीम ने अपने कौशल से उत्तर प्रदेश की नानापारा टीम को ट्राई ब्रेकर में जबरदस्त पराजित किया। निर्णायक रवी हरदुआ एवं शिवम सोनोधीया थे। इस अवसर पर आयोजन समिति अध्यक्ष जयराम रघुवंशी, भानूप्रकाश

तिवारी, शेर खान, जयप्रकाश माहेश्वरी, संजय खंडेलवाल, सचिव पवन सिंह चौहान, संयोजक अश्वनी सरोज, शंकरलाल मालवीय, अभिषेक चौहान, सौरभ तिवारी, अभिनव पालीवाल, दादराम कुशवाहा, एकम राजपूत, दिलीप परदेशी, अंकुश जायसवाल, शेख आरिफ, किशोर काका, मनोज गोलाानी, दीपक तिवारी, अनुज जायसवाल आदि उपस्थित थे।

90कोणीय रास्ते में होते रहते हैं हादसे

ग्राम लांगाबम्होरी के पास शिफ्ट कार 90 कोणीय रास्ते में गिरी एक की मौत

सोहागपुर। भोपाल से पचमढ़ी जाते सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम लांगाबम्होरी के पास 90 कोणीय ब्लैक स्पॉट पर शिफ्ट कार खाई में गिर गई। इस कार में भोपाल के चार युवक अंशुल प्रजापति, दीपक अहिरवार, रोहित कटारे एवं आकाश साहू सवार थे। उक्त कार 90 कोणीय रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में आकाश साहू पिता हरिप्रसाद साहू की कार में दबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने पंचनामा के बाद परिजनों को सौंपा दिया। पुलिस ने मामला कायम कर जांच में लिया है।उल्लेखनीय है कि सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय सोहागपुर के समीपवर्ती ग्राम लांगाबम्होरी के 90 कोणीय के मोड़ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों पूर्व एक बस दुर्घटना हुई थी। जिसमें करीबन 15 से अधिक यात्रियों की मौतें हो गई थी। तब जोर शोर से कहा गया था कि कुछ ही दिनों में 90 कोण बिलेक स्पॉट



के रास्ते को सीधा करवा दिया जाएगा। ताकि नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन यह दूर की कोढ़ी सिद्ध हुआ है।नागरिक अब भी लांगाबम्होरी के सीधे रास्ते बनने की राह देख रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस 90 कोणीय ब्लैक स्पॉट पर आए दिन जो हादसे होते रहते हैं। इन हादसे में अधिकांश हादसे अन्य नगरों के वाहन होते हैं। जिसमें वाहन चालकों को यह अंदेश ही नहीं हो पाता कि यहां रास्ता कितना ख़तरनाक है?

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट : हेमंत खंडेलवाल

भाजपा द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद में बोले प्रदेश अध्यक्ष

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर के रामकृष्ण बगिया लॉन में आयोजित बजट प्रस्तुतिकरण एवं व्यापारी संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है। वह सिर्फ एक वर्ष का बजट नहीं बल्कि अगले 10 साल में भारत का भविष्य कैसा होगा उसे ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया बजट है। यह बजट देश की दिशा तय करने वाला एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि सुधार, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट मे की गई घोषणाओं के अनुसार देश में तीन नए आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे, मेडिकल टूरिज्म के 5 नए हब बनेंगे। नए टेक्सटाईल पार्क की स्थापना होगी, 22 नए जलमार्ग प्रारंभ किए जाएंगे एवं 7 हवाई स्पीड रेल कारिडोर का निर्माण किया जाएगा। छोटे शहरों में स्थित तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा। लखपति दीदीयों की आय बढ़ाने के लिए छोटे छोटे विक्रय केन्द्र खोले जाएंगे।



उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में रोजगार सृजन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आने वाले दशक में भारत वैश्विक निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र बनेगा। पुराने औद्योगिक सेक्टर को जीवित किया जाएगा। मछली पालन के लिए 500 अमृत जलाशय बनाए जाएंगे। डेरी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। विदेश यात्रा सस्ती होगी। पर्यटन को

बढ़ावा देने के लिए बुद्ध सर्किट का निर्माण होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि यह बजट विश्वास और विकास का बजट है। बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह बजट देश को नई दिशा देने वाला बजट है। जिसमें सभी सेक्टरों एवं समाज के सभी वर्गों के विकास की चिंता की गई है। विधायक डा.योगेश पंडाग्र ने कहा कि बजट में 5 रिजनल मेडिकल हब बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य पेशावरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन एवं स्थापना का निर्णय भी स्वागत योग्य है। कैन्सर सहित कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली कई दवाइयों का सस्ता किया गया है। जो निश्चित ही एक राहत देने वाला कदम है। इस बजट का जितना भी स्वागत किया जाए कम है। इस अवसर पर ब्रज कपूर, गजानंद मोटवानी, नवीन तातेड़, प्रेमशंकर मालवीय, श्रीचंद्र हिराणी, मंजीतसिंह साहनी, रमेश मिश्रा, नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर सहित प्रमुख व्यापारी, प्रोफेशनल एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन केन्द्रीय बजट प्रचार अभियान के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने किया एवं अंत में आभार जिला कोषाध्यक्ष दीपक सलूजा ने व्यक्त किया।

‘आपरेशन मैट्रिक्स’ के तहत म्यूल बैंक खातों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश

9 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नगद बरामद, 13 लाख की राशि फ्रीज, 19 मोबाईल फोन सहित दर्जनों चेकबुक-एटीएम कार्ड बरामद

देवास। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर सेल मुख्यालय ए.साँई मनोहर के निर्देशन पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ‘आपरेशन मैट्रिक्स’ की शुरुआत की गई है। इस विशेष अभियान का प्राथमिक लक्ष्य उन संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित कर एजेन्टों तथा किराये पर खाता देने वाले लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना है, जिनका उपयोग साइबर फ्राड के जरिए लूटी गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है। इस आपरेशन के केंद्र में वे कमीशन पर किराये से लगाये गये खाते हैं, जिन्हें साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए ढाल बनाते हैं।

इसी कड़ी में ‘आपरेशन मैट्रिक्स’ के तहत पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों तथा जिला साइबर सेल देवास को आदेश दिया गया है कि ‘ऑपरेशन मैट्रिक्स’ की मंशा के अनुरूप देवास जिले को ‘म्यूल अकाउण्ट’ मुक्त बनाया जाना है। जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के निर्देशन मे पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को ‘म्यूल अकाउण्ट’ देवास से आपरेट होने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 08.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा होटल ‘श्री जी’ गंगानगर देवास मे तत्काल दबिश दी गई। होटल के एक कमरे में सायबर फ्राड से सम्बंधित पाँच आरोपियों मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन,पियुष बिल्लोरे,शुभम जोशी,आशीष जैन उर्फ गोलू व गौरव जैन को अभिरक्षा मे लेकर पंछताछ की गई । आरोपीगण से प्राप्त जानकारी और मोबाइल फोन तथा बैंक स्टेटमेंट खंगाले गये तो पाया गया कि मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन के दो करंट अकाउण्ट में करोड़ों का ट्रान्जेक्शन हुआ है । करोड़ों रुपयों के इन ट्रान्जेक्शंस का कोई भी स्पष्टीकरण पाँचो आरोपीगण के पास नहीं था ।

आरोपीगण ने पुछ्ताछ पर बताया कि



वह सभी पाँचो लोग ऐसे साइबर ठगों के लिये काम करते हैं जो अपनी पहचान छुपाकर टेलीग्राम के जरिये देश के अलग अलग शहरों से सम्बंध रखने वाले भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाभ दिलाने का लालच देकर खातों मे करोड़ों रुपये का ट्रान्जेक्शन करवाते हैं तथा रफू चक्कर होकर उनसे दूरी बना लेते हैं । औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/2026 थारा 318(4), 316(5) BNS वृद्धि धारा 6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया । आरोपीगण से जप्त सामग्री,बैंक अकाउण्ट्स डिटेल्स आदी तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर डिजिटल ट्रेल का पीछ कर इन पाँच आरोपीयों के अलावा साइबर ठगों को म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 04 सिनियर एजेन्ट्स मंजीत सिंह भाटी उर्फ राज सोनी,नितेश बिरला,जितेन्द्र राजपुत उर्फ जितु उर्फ लेफ्टी व शुभम परमार उर्फ शुब्बु को गिरफ्तार किया गया है ।

आरोपीगण के कब्जे से अभी तक कुल 19 अत्याधुनिक एंड्राइड मोबाईल फोन कीमती करीबन 4,77,000/- रुपये, नगदी 2,00,000/- रुपये, 1 वायफाय बाक्स,2 चेकबुक,2 ए.टी.एम.कार्ड,2 पेन कार्ड,1 आधार कार्ड,1 नोटबुक,1

जमापची, 2 सील मुहर तथा घटना मे प्रयुक्त एक टाटा नेक्शोन कार क्रमांक MP22ZA1009 कीमती करीबन 10 लाख रुपये कुल मश्रुका करीबन 16,77,000/- (सोलह लाख सत्तरह हजार रुपये) का मश्रुका जप्त किया गया तथा खातों में सायबर फ्राड से संबंधित करीबन 13 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज करवाई गई । पुलिस ने अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है । पुलिस अन्य संदेहियों के सम्बंध मे भी जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है ।

जप्त सामग्री दस्तावेज:- (2 चेकबुक, 2 ए.टी.एम. कार्ड, 2 पेन कार्ड,1 आधार कार्ड,1 नोटबुक,1 जमापची) उपकरण:-19 अत्याधुनिक एंड्राइड मोबाइल फोन,1 वायफाय बाक्स व 2 सील मुहर (कीमत लगभग 4,77,000/- रुपये) धनराशि:- 2 लाख रुपये नगदी तथा साइबर फ्रॉड से सम्बंधित करीबन 13 लाख रुपये की राशी फ्रिज करई गई। वाहन:- टाटा नेक्शोन कार क्रमांक MP 22 ZA1009 (कीमत लगभग 10 लाख रुपये) कुल जप्त मश्रुका: ₹. 29,77,000/- (₹. 16,77,000/- जप्त एवं ₹. 13,00,000/- बैंक खाते में फ्रीज) गिरफ्तार आरोपी:

- मुनेश्वर उर्फ मनीष पिता लक्ष्मणप्रसाद सेन उम्र 38 साल नि.धर्मपुरा,वार्ड क्र.39 पृथ्वीराज वार्ड, दमोह (म.प्र.)।
- पीयुष पिता अनिल बिल्लोरे उम्र 24 साल निवासी म.नं. 183 विजयश्री नगर थाना एरोडूम जिला इंदौर ।
- शुभम पिता प्रकाश जोशी उम्र 29 साल निवासी न्यू विज्ञान नगर डाइट रोड़ जिला टोंक (राजस्थान) ।
- आशीष उर्फ गोलू पिता अशोक कुमार जैन उम्र 42 साल निवासी असाटी वार्ड क्र.01 पुराना थाना दमोह (म.प्र.)
- गौरव पिता खुशालचंद्र जैन उम्र 42 साल निवासी जैन मंदिर के पास,वार्ड क्र. 01 मेन रोड़,धनोरा जिला सिवनी हाल मुकाम राममनोहर लोहिया वार्ड,अंधेरदेव जबलपुर (म.प्र.) ।
- मंजीत पिता राजू सिंह भाटी उम्र 31 साल निवासी म.नं. 110-ए,नगीन नगर, थाना एरोडूम जिला इंदौर ।
- नितेश बिरला पिता भागीरथ बिरला उम्र 26 साल निवासी गोवर्धन पैलेस, शिरपुर धार रोड़,इन्दौर ।
- हाल मुकाम म.नं. 58 राधाकृष्णविहार कालोनी एकतानगर, नंदबाग रोड़, इन्दौर ।
- जितेन्द्र उर्फ जितू उर्फ लेफ्टी पिता सुरेश राजपूत उम्र 27 साल निवासी 13 न्यू गांधी पैलेस, इन्दौर हाल मुकाम फ्लेट नं. 201, सी ब्लॉक, गायत्री कुंज कालोनी इन्दौर ।
- शुभम उर्फ शुब्बु पिता मदनलाल परमार उम्र 28 साल निवासी म.नं. 923/बी, राजनगर इन्दौर ।
- हाल मुकाम फ्लेट नं. 201, सी ब्लॉक, गायत्री कुंज कालोनी इन्दौर ।
- सराहनीय कार्य: उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया,उनि राकेश चौहान, गौरव नागावत,नरेन्द्र अम्करे, राधेश्याम मगर, मप्रआर निर्मला पाल,आर अजय जाट, लक्ष्मीकांत शर्मा,नरेन्द्र सिरसाम, यशपाल रायपुरीया,अर्पित जायसवाल, अजय साल्वे एवं साइबर सेल से प्रआर शिवप्रताप सिंह सेंगर,सचिन चौहान व गीतिका कानूंगो सराहनीय भूमिका रही ।

राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव में छार धार जिले के फूल



धार। उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशाअुसार राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव-2026 का आयोजन गुलाब उद्यान परिसर, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। पुष्प महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों द्वारा विविध प्रकार के फूलों की आकर्षक प्रदर्शनियाँ लगाई गईं। इस अवसर पर धार जिले के कृषकों द्वारा पॉलीहाउस तकनीक से उगाई गई विभिन्न प्रजातियों के फूलों की भव्य प्रदर्शनी प्रस्तुत



की गईं। प्रदर्शनी में डच रोज, डिवाइन रोज, जरबेरा, लिसियम्स, जिम्सोफेला, ब्लू एवं रेड डेजी, सनपलावर, लिमोनियम, क्रिसेंथेमम, एस्टर सहित अन्य फूल शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर उद्यानिकी विभाग एवं कृषकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं प्रयासों की सराहना की गई। इस आयोजन में धार जिले के कृषकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पुष्प प्रदर्शनों को उत्कृष्टता के आधार पर कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे जिले का नाम राज्य स्तर पर गौरवान्वित हुआ।

धार में पिंग लाइसेंस कैंप आयोजित 2 छात्र, 63 छात्राओं के लाइसेंस बने

परिवहन और महिला एवं बाल विकास विभाग का साझा आयोजन



धार। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के लिए लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए।

शिविर के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की कर्मचारी खुशी पाय्या, सहायक वर्ग-3 एवं प्रदीप सोलंकी, सहायक वर्ग-3 द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत

छात्राओं एवं छात्रों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रतिनिधि चेतना राठौर द्वारा महिलाओं को सड़क सुरक्षा, सुरक्षित आवागमन एवं स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता, गति सीमा का पालन, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन के प्रयोग से बचने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में विस्तार से समझाया।

पिंग लाइसेंस कैंप में छात्र- छात्राओं एवं महिलाओं के लिए

लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए, जिसमें 2 छात्र एवं 63 छात्रा सहित कुल 63 छात्र-छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। शिविर में मौके पर ही दस्तावेज सत्यापन कर आवेदन को आत्मनिर्भर बनाना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें वैधानिक रूप से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना है। महाविद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना की।

आम बजट 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी रविवार को कहा कि सरकार ने कोरी बयानबाजी के बजाय सुधारों का रास्ता चुना है। उन्होंने लोकसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि देश 'विकसित भारत' बनने की दिशा में कदम उठाता रहेगा। वित्त मंत्री ने 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की। यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। यह उभरता भारत का बजट बताया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर बनाएं। नागरिक सामर्थ्य बढ़ाने पर जोर दिया। पर्यटन को प्रोत्साहन से युवाओं को अवसर।

उभरते भारत के सपने को संजोता बजट



- रक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान, कैंसर से जुड़ी दवाइयां सस्ती, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा
- पीएम मोदी बोले- यह बजट विकसित भारत की उड़ान

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में

भंडारण (सीसीयूएस) दिसंबर 2025 में जारी किए गए रोडमैप के अनुरूप, मैं अगले पांच वर्षों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) तकनीकों के विकास,

इस बजट में किसानों को मिले अनगिनत तोहफे
* महंगी फसलों पर फोकस
* पहाड़ी इलाकों में खेती को बढ़ावा
* चंदन की खेती पर भी दिया जोर
* भारत विस्तार की शुरुआत
* पशुपालन में रोजगार को बढ़ावा
* एफपीओएस को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15 प्रतिशत बढ़ा, 17 कैंसर मेडिसिन ड्रग्स फ्री, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।



15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिपोर्ट नौवां बजट पेश करने से पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत की उड़ान है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, कार्बन कैप्चर, उपयोग और

विस्तार और अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च स्तर की तैयारी हासिल करने के लिए 20,000 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखती हूं। यह पहल पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन उद्योग में लागू की जाएगी।

बजट में द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों एवं बौद्ध सर्किट पर जोर देने से असम को लाभ मिलेगा



पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, पांच पूर्वोत्तर राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार के बजट में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के अवसंरचना विकास पर दिए गए जोर और बौद्ध सर्किटों की घोषणा से असम को लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित करना राज्य के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यम मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी शहरों और यहां तक ? कि मंदिर-नगरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और

बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं

- * इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- * कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 प्रतिशत शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्रग्स फ्री।
- * 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
- * आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
- * 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
- * 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेनर क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी।
- * करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।
- * इनकम टैक्स-स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा
- * स्वास्थ्य-कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्रग्स हटेंगी, इलाज सस्ता होगा
- * आयुर्वेद-भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी।



क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?



- सोलर उपकरण, जूते, मोबाइल बैटरी होंगे सस्ते।
- कैंसर 17 दवाएं सहित 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती।
- शुगर की दवाई सस्ती होगी
- विदेश यात्रा पहले से सस्ती होगी।
- सीएनजी और बायोगैस भी सस्ती
- स्मार्टफोन और टैबलेट होंगे सस्ते
- बीडी सस्ती हुई
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंपोर्ट की गई दवाएं और औषधियां
- माइक्रोवेव ओवन के लिए जरूरी कंपोनेंट
- विमानों के इंजन सहित पाट या कंपोनेंट
- सोलर ग्लास सामग्री
- न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट किए गए सामान
- क्रिटिकल मिनिरल के लिए पूंजीगत सामान

ये प्रोडक्ट हो जाएंगे महंगे



- कम कीमत वाले इंपोर्ट किए गए छाले
- पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
- एटीएम या कैश डिस्पेंसर मशीन और उसके पाट व कंपोनेंट
- विदेशी वरु के लिए फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग उपकरण
- चिड़ियाघर के लिए इंपोर्ट किए गए जानवर और पक्षी
- अमोनियम फॉस्फेट या नाइट्रो-फॉस्फेट उर्वरक और नेपथा उर्वरक
- कॉफी रोस्टिंग, ब्लूइंग या वेंडिंग मशीनें
- अरंडी का ऑयल केक
- शराब
- स्कैप
- खनिज
- सिगरेट।

बजट 2026 वो फैसले जो बचाएंगे आपका पैसा

- बजट में मिडिल क्लास परिवार को मिली बचत की सुरक्षा- मिडिल क्लास के लिए बजट में सबसे बड़ा फोकस टैक्स और कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर रहा। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लेपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लैरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने

वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे। विदेश से स्थायी रूप से लौटने वालों के लिए घरेलू सामान लाने की ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा सभी पर्सनल इंपोर्ट्स और गिफ्ट्स पर एक समान कस्टम ड्यूटी लागू की जा रही है, जिससे भ्रम खत्म होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को



- बजट में स्टूडेंट को विदेश में पढ़ाई के लिए मिला आसान मौका- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और

राशि पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 5 प्रतिशत होता था। इससे छात्रों पर शुरूआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इंपोर्टेड स्टडी मटीरियल या पार्सल की विलयर्स भी तेज होगी।

- बुजुर्गों को बजट में आय सुरक्षा मिली- सीनियर सिटीजनस के लिए बजट में कम कागजी काम, ज्यादा सूकून की सोच दिखाई देती है। अब डिजिटल और ब्याज पर टीडीएस से राहत के लिए फार्म

15 प्रतिशत/15एच एक ही विंडो से जमा किया जा सकेगा। छोट्टे करदाताओं के लिए लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है वो भी नाममात्र शुल्क के साथ होगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

बजट पर किसने क्या कहा

आशा और आकांक्षाओं का बजट है: सीएम योगी

सीएम योगी ने केंद्रीय बजट 2026 कहा- आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट है। इसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा।



विकसित भारत बजट :अमित शाह



और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी का हर भारतवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन।

यह एक हम्पटी-डम्पटी बजट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह एक 'हम्पटी-डम्पटी बजट' है, सिर्फ शब्दों का खेल है, यह महिला-विरोधी, किसान-विरोधी और शिक्षा-विरोधी है। केंद्र देश की आर्थिक संरचना को नष्ट करना चाहता है।



पीतल के गहने पहनने पड़ेंगे

केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें सोने पर पीतल के गहने पहनने पड़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह ऐसा बजट नहीं है जो किसी को राहत प्रदान करे।



बजट पर राहुल गांधी बोले संसद में बोलूंगा

केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, लोकसभा में विपक्ष के सदस्य राहुल गांधी ने कहा, मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का उपयोग करते हुए बोलूंगा।



रामदास अठावले

केंद्रीय बजट 2026-27 पर आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने कहा, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। यह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों प्रदान करेगा।

शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, हमें बहुत कम जानकारी मिली। 3-4 मुख्य बिंदु थे, लेकिन हम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का इंतजार कर रहे थे। यह कहाँ है? हम इसे केरल में चाहते थे। आयुर्वेद की हमारी एक लंबी परंपरा रही है।

सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भर के लिए

केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। इसके अलावा, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के विजन को मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं, इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं... ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद, इस बजट ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को बल दिया है।



